

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 134/2022

आरसीएमएस नं. 2022/00134

अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

जगतार सिंह पुत्र श्री तोता सिंह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) —अपीलार्थी

बनाम

1. गुरजण्ट सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

—असल रेसपोडेण्ट

2. सुखमन्द्र सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—तरतीबी रेसपोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 21.12.2021, संशोधित आदेश दिनांक 31.01.2022

प्र. सं. 400/2021 अनवान गुरजण्ट सिंह बनाम जगतार सिंह आदि

उपस्थिति:-

श्री खुशप्रीत सिंह संघू, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण, अभिभाषक रेसपोडेण्ट संख्या 1

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक

karis
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



निर्णय

दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेण्ट सं० 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनतर्गत एक प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 3 यूटीएस, खाता संख्या 119/38 व चक 1 यूटीएस खाता संख्या 96/38 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा घरू बंटवारा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजी प्राप्त हुई है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में आराजी अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज होने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या पूर्व में 05 बीघा भूमि बिना किसी जरूरत के बेचान किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध स्थगन आदेश बाबत अनुतोष चाहा जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 31.01.2022 को संशोधित आदेश जारी किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट सं० 1 द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पैतृक समति हो। विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश के तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को किस प्रकार प्रमाणित माना है यह स्पष्ट नहीं किया है। विचारण न्यायालय के संशोधित आदेश के उपरान्त मगर जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है। प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट के आधिपत्य व धारण की आराजी को अपने इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है तथा अपने आधिपत्य व धारण की आराजी पर ऋण सुविधा प्राप्त करने व उसको बेचान करने की सुविधा में अन्य कोई पक्ष बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। अपीलान्ट के हक हिस्सा की आराजी में रेस्पोंडेण्ट का हक हिस्सा निहित नहीं है। अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी अपनी माता व चार बहिनों से पंजीकृत हक त्याग से प्राप्त हुई है। प्रश्नगत आराजी अपनी बहिन से प्राप्त होने के कारण अपीलान्ट की स्वअर्जित


Levio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



सम्पत्ति है जिसमें किसी का हक हिस्सा निहित नहीं है। रेस्पोजेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं की। अपीलान्ट को सूचना दिये बिना संशोधित आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की शुरु से ही जानकारी रही है। अपीलान्ट ने देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलान्ट ने न्यायालय को मुगालता में रखकर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है तथा उक्त स्थगन आदेश प्राप्त करते ही अपीलान्ट ने रेस्पोजेण्ट सं0 1 के हक व हिस्सा को मारने के आशय से दिनांक 05.05.2021 को चक 3 यूटीएस की 3 बीघा कृषि भूमि का बेचान कर दिया है। जबकि उक्त कृषि भूमि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के हक व हिस्सा की थी। अपीलान्ट के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोजेण्ट का हक हिस्सा है जिसे अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोजेण्ट के पक्ष में है अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. विचारण न्यायालय ने रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ने धारा 212 आरटीएक्ट के प्रार्थना-पत्र अस्थाइ निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिसमें दिनांक 12.12.2021 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया एवं दिनांक 31.01.2022 को संशोधित आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय में दिनांक 06.04.2022 को अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद में हक अधिकारों का निर्धारण होना है मगर प्रथम दृष्टया अपीलान्ट एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार है,


राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



अभिलिखित खातेदार कातशकार होने के कारण उसे अपने आधिपत्य एवं धारण की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के पूर्ण स्वतंत्रता है। जिसके विरुद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया। जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को स्थगन आदेश पर सुनकर पुनः निर्णय पारित करना चाहिए था क्यों कि पूर्व में स्थगन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2021 व संबंधित आदेश दिनांक 31.01.2022 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर स्थगन प्रार्थना-पत्र पर एक माह में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।

पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया



4/7/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्वा अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़